

Statement regarding India-US Bilateral Trade Agreement

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी, 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से, भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। (व्यवधान)

इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। (व्यवधान)

इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। (व्यवधान) अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे, जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार-विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। (व्यवधान) उसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। (व्यवधान) यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूँ कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है।

साथ ही, यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज), उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। (व्यवधान) उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगी और भारत के मेक-इन-इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन-इन-इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट-इन-इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। (व्यवधान)

यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और 'विकसित भारत-2047' की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार हैं और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर

काम करेंगे, ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके । (व्यवधान) समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी । माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी, जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाये गए हैं ।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है । (व्यवधान)

वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है । (व्यवधान) भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं । (व्यवधान)

अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं । (व्यवधान) दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं । (व्यवधान)

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र और परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी । (व्यवधान) अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में, बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा । (व्यवधान)

हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा । (व्यवधान) विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा । (व्यवधान) यह समझौता भारत की जनता और राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा । (व्यवधान) यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है । (व्यवधान) हम अपने देश के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे ।

धन्यवाद महोदय ।
